पेगासस जासूसी: रंगभेद के साथ कूटनीति

जुलाई 2021 में, फोर्बिडन स्टोरीज़ और एमनेस्टी टेक के पेगासस प्रोजेक्ट में खुलासा किया गया कि इज़रायल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर के किस हद तक दुनिया भर के विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की जासूसी की गई थी। भारत में 300 से ज़्यादा लोगों के नाम संभावित और पक्के टारगेट लोगों की सूची में थे। यह एक तथ्य है कि एनएसओ ग्रुप अपने उत्पाद सिर्फ़ सरकारों को बेचता है, मगर मोदी सरकार ने नागरिकों की टार्गेटेड जासूसी के आरोपों पर कोई सफ़ाई नहीं दी है। सरकार द्वारा स्पाईवेयर के इस्तेमाल से इनकार न करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के एक कमेटी का गठन किया है।

न्यू यॉर्क टाइम्स की एक हालिया जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि एनएसओ ग्रुप का पेगासस उस समझौते का हिस्सा था जो प्रधानमंत्री ने 2017 की इज़रायल यात्रा के दौरान किया था। रिपोर्ट बताती है कि कैसे इजरायल ने फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ अपने रंगभेद, क़ब्ज़ा और सेटलर औपनिवेशिक शासन को 'वाइटवॉश' करने में मदद करने के लिए एक राजनयिक उपकरण के रूप में पेगासस को तैनात किया है।

रंगभेद इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। फ़िलिस्तीनी कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने इज़रायली रंगभेद फ़्रेमवर्क को दशकों से देखा है, और अब बाक़ी दुनिया भी इसमें जुड़ रही है। पौरव राष्ट्रपति और वैश्विक दक्षिण के कई सांसदों और ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने भी यह माना है कि इज़रायली सत्ता रंगभेदी है और संयुक्त राष्ट्र को उसके द्वारा किये जा रहे इंसानियत के ख़िलाफ़ अपराधों की जांच करनी चाहिये।

इस बढ़ते विरोध के बावजूद भारत की दक्षिणपंथी सरकार 21वीं सदी की रंगभेदी सत्ता के साथ अपने संबंध मज़बूत करने में लगी हुई है। इस साल भारत और इज़रायल के संबंधों को 30 साल हो रहे हैं। एक वक़्त पर भारत फ़िलिस्तीन की आज़ादी और दक्षिण अफ़्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष का समर्थक था, मगर आज भारत इज़रायली शस्त्रों के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक और इज़रायल का क़रीबी संबंधी भी है। बीजेपी की हिंदुत्व सत्ता के 7 सालों में इज़रायल के साथ ये संबंध वैचारिक स्तर पर भी गहरे हुए हैं। हिंदुत्व और ज़ियोनिज़्म दोनों विचारधाराएं हिंसक प्रवृत्ति की हैं। यह समानताएं दमनकारी नीतियों में दिखती हैं।

एक तरफ़ नागरिकता संशोधन अधिनियम इज़राली लॉ ऑफ़ रिटर्न जैसा दिखता है, और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने के बाद तो भारतीय राजनयिकों ने यह तक कहा है कि इस क्षेत्र में भारत को इज़रायल जैसे सेटलमेंट्स बनाने चाहिये।

भारत और इज़रायल जैसे दो अलगाववादी शासनों के बीच गहरा गठजोड़ हैरान नहीं करता है। प्रत्येक सरकार द्वारा उत्पीड़ित लोगों के बीच एकजुटता समान रूप से स्पष्ट है। मोदी शासन की विभाजनकारी नीतियों का विरोध करने वाले भारतीय भी इज़रायल के संस्थानों के साथ-साथ उन अंतरराष्ट्रीय निगमों के ख़िलाफ़ बहिष्कार, विभाजन और प्रतिबंध (बीडीएस) अभियानों का समर्थन करते हैं जो इसके क़ब्ज़े और रंगभेद से लाभ उठाते हैं। फ़िलिस्तीनी किसानों ने हाल ही में सरकार को अपने कॉर्पोरेट समर्थक

क़ानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर करने वाले भारतीय किसानों के साथ अपनी एकजुटता ज़ाहिर की। संघर्षों की यह एकता लगातार बढ़ रही है।

इज़रायल की स्पाइवेयर तकनीक को फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करके विकसित किया गया है। स्पाइवेयर व्यापार दमन के लिए तैयार किया गया है, और इज़राइल इसके केंद्र में है क्योंकि इसकी औपनिवेशिक और रंगभेदी शासन इसे एक अधीन लोगों के ख़िलाफ़ तैनात करता है। इस प्रकार विकसित की गई तकनीक विश्व स्तर पर दमनकारी सरकारों को बेची जाती है। मोदी सरकार के ध्रुवीकरण वाले हिंदुत्व के एजेंडे को लोगों के प्रतिरोध से ख़तरा है - यह असंतोष के प्रति असहिष्णु है और इसलिए कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की टार्गेटेड निगरानी का सहारा ले रहा है। हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा में और विरोध करने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता में, हम मांग करते हैं कि हमारे सार्वजनिक संसाधनों को एक रंगभेदी शासन से खरीदी गई निगरानी तकनीक पर ख़र्च न किया जाए।

एनएसओ ग्रुप को बैन किया जाए। रंगभेद का समर्थन बंद किया जाए।